मॉडर्न डीपीएस मार रहा डकैती, बच्चों की ऑनलाइन क्लास रोकी

पैरंट्स के ईमेल और वाट्सऐप मैसेज का जवाब तक देने को तैयार नहीं मैनेजमेंट

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः शहर के स्कूलों की दादागीरी बढ़ती जा रही है लेकिन हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग किसी भी स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने में नाकारा साबित हो रहा है। ताजा मामला ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न डीपीएस स्कूल का है जो सरेआम पेरंट्स पर डकैती मार रहा है और विभाग का तंत्र चुप है। अब उसने कई बच्चों की ऑनलाइन क्लास ही कई सारी वजहों से रोक दी है। इन बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल से ईमेल व वाट्सऐप के जरिए, जुबानी भी पूछा तो स्कूल कोई संतोषजनक जवाब देने को तैयार नहीं है।

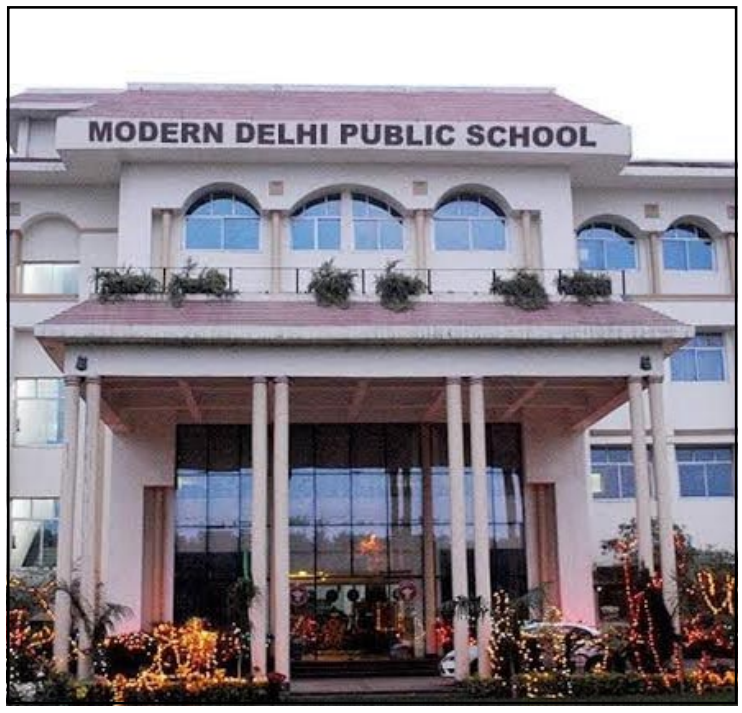

क्लास और परीक्षा से रोका

कमल गुप्ता की दो बेटियां सार्वी गुप्ता और दिशा गुप्ता सेक्टर 87 ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मॉडर्न डीपीएस की छात्राएं हैं। अप्रैल 2021 में कमल गुप्ता के पास स्कूल की ओर से एक नोटिस आया, जिसमें उनसे 31050 रुपये दिशा गुप्ता की फीस और 28650 रुपये सार्वी गुप्ता की फीस जमा कराने को कहा गया। यह फीस पिछले साल इन्हीं बच्चियों के लिए दी गई फीस से बहुत ज्यादा थी तो कमल गुप्ता ने स्कूल को ईमेल में लिखा कि कृपया बताएं कि ये फीस किन-किन मदों में ली जा रही है। यह ईमेल उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 20 मई 2021, 26 मई, 29 मई और 8 जून 2021 को लिखा।

कमल गुप्ता ने सीएम से लेकर पीएम तक भेजी गई शिकायतों में लिखा है कि यह स्कूल एक तरफ क्लास टीचर, काउंसलर को फीस का ब्रेकअप वाट्सऐप पर बता रहा है लेकिन उन्हें ईमेल पर भेजने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा फीस ली जा रही है तो पैरंट्स तो स्कूल से पूछताछ करेगा ही। कमल गुप्ता का आरोप है कि उनकी ज्यादा लिखा-पढ़ी का नतीजा यह निकला कि स्कूल ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया कि आपकी दोनों बेटियों की ऑनलाइन क्लास रोक दी जाएगी। हर हालत में फीस जमा करना होगी।

मॉडर्न डीपीएस ने पिछले साल (2020-21) कमल गुप्ता से 86400 रुपये फीस वसूली थी लेकिन आज तक उन्हें इन पैसों की रसीद स्कूल ने नहीं दी है। हालांकि वो स्कूल को इस बारे में कई बार लिख चुके हैं लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल, मैनेजर और अन्य स्टाफ जवाब ही नहीं देते।

अब 2 जुलाई 2021 से मॉर्डन डीपीएस ने सार्वी गुप्ता और दिशा गुप्ता की आनलाइन क्लास ही रोक दी है। इस बारे में भी उन्होंने सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री, हरियाणा शिक्षा विभाग तक को लिखा लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।

स्कूल के अजीबोगरीब तर्क

इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी रीतू चौधरी के पास भी पहुंची। उन्होंने स्कूल से इस मामले में जवाब मांगा। मॉडर्न डीपीएस के दो अधिकारी डीईओ के पास जवाब देने पहुंचे। स्कूल ने डीईओ को बताया कि कमल गुप्ता और उनकी पत्नी अच्छा कमाते हैं, इसके बावजूद फीस नहीं दे रहे हैं। उन्होंने फीस नहीं जमा कराई है इसलिए हमने उनकी ऑनलाइन क्लास रोक दी है। लेकिन स्कूल इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर जो फीस वो इस साल वसूलना चाहता है, उस फीस का ब्रेकअप क्या है। इसके अलावा भी स्कूल ऐसे पैरंट्स पर तरह-तरह के आरोप लगा रहा है कि वे लोग नेतागीरी कर रहे हैं। ऐसे आरोप और भी प्राइवेट स्कूल वालों ने पेरंट्स पर लगाए हैं लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं हैं कि वे जो डकैतियां मार रहे हैं, उसका हिसाब पैरंट्स को क्यों नहीं देंगे।

मजदूर मोर्चा ने अपने पिछले अंक में इसी तरह डीएवी सेक्टर14 और आयशर स्कूल में बढ़ाई गई फीस का मुद्दा उठाया था। लेकिन हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। क्योंकि तमाम राजनेताओं को शिक्षा व्यापारियों से, लूट कमाई का हिस्सा मिलना रहता है।

फर्जी पीटीए भी बना रखी है

मॉडर्न डीपीएस समेत कई निजी स्कूलों ने फर्जी पैरंट्स टीचर्स एसोसिएशन (पीटीए) भी बना रखी है। जब कोई सरकारी एजेंसी वगैरह निरीक्षण के लिए आती है या मीडिया के सामने उसी फर्जी पीटीए को आगे कर दिया जाता है। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले पैरंट्स तक हैरान हैं कि वे लोग खुद तो पीटीए में नहीं हैं तो आखिर कौन लोग हैं जो पीटीए में रखे गए हैं और सिर्फ वे ही बोलते हैं। स्कूल किसी और को बोलने ही नहीं देता। हालांकि नियम तो यह है कि हर निजी स्कूल में पीटीए जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटीज के यहां रजिस्टर्ड होना चाहिए लेकिन किसी भी एक स्कूल में रजिस्टर्ड पीटीए नहीं है।

बैंक डकैती को न्योता देती व्यवस्था

पलवल (म.मो.) 3 मोटर साइकिलों पर 5 युवक एक्सिस बैंक की ब्रांच में आते हैं और महज 4-5 मिनट में 95 लाख रूपए लूट कर चलते बनते हैं, न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। बेरोजगारी व भूखमरी के इस दौर में उन्हें इससे बढ़िया व सरल और कोई धंधा शायद नजर नहीं आया। सरकारी सांठ-गांठ से जब कॉर्पोरेट जगत के लोग बैंकों से हजारों करोड़ लेकर चंपत हो रहे हैं और कुछ तो इतनी पक्की सांठ-गांठ किये हुए हैं कि चंपत होने की बजाय यहीं डटे रहकर लोन पर लोन लेकर डकारे जा रहे हैं, सरकार है कि उन्हें बट्टे खाते डाले जा रही है।

उक्त 5 नवयुवकों के पास न तो इतनी बुद्धि थी और न ही सरकार से सांठ-गांठ करने का जुगाड़ कि बैंक उन्हें सीधी उंगली से 95 लाख दे देता लिहाजा उन्होंने ऊंगली जरा से टेढ़ी की और ले उड़े माल। पकड़े गये तो जेल काट लेंगे वरना तो मौज ही मौज।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उक्त पांच में से मात्र तीन ही बैंक के भीतर एक्शन करने पहुंचे थे और 2 बाहर से उन्हें कवर दे रहे थे। बैंक मे इस समय मौजूद 15 लोगों (कर्मचारी व ग्राहक) में से किसी की हिम्मत उन्हें रोकने-टोकने की न हुई।

जाहिर है कि कोई पंगे में पड़कर अपने आप को जोखिम में डालना नहीं चाहता और तो और इस समय बैंक के बाहर खड़े

10-20 लोग तमाशबीन बने डकैती का सीन देखते रहे। लेकिन किसी ने भी पुलिस को सूचित करने का 'जोखिम' नहीं उठाया।

यहां 'जोखिम' शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया है कि आम आदमी पुलिस को सूचित करने को इसी नजरिये से देखता है। वह यह मानकर चलता है कि कोई डकैत भले ही न पकड़ा जाये उसे तो पुलिस जरूर पकड़ लेगी और पूछताछ के नाम पर उसकी रेल बना देगी। हमारी पुलिस की यह आम शौहरत है जिसके चलते आम लोग पुलिस से कन्नी काटकर चलते हैं।

बैंकों की लापरवाही व पुलिस की कोताही

लगभग सभी बैंकों में गनमैन बहुत ही लापरवाही से बैठा या ऊंघता मिलेगा या फिर बंदूक साइड में रखकर ग्राहकों से घिरा मिलेगा।

ऐसे में कोई भी उसकी बंदूक छीनकर डकैती को अंजाम दे सकता है। बैंकों के अलार्म व सीसीटीवी कैमरे भी अक्सर काम नहीं कर रहे होते। मौजूदा मामले में गनमैन के पास गन तो थी ही नहीं, हां सीसीटीवी कैमरे जरूर काम कर थे, लेकिन उनका कोई लाभ इसलिये नहीं मिल सका क्योंकि कोरोना के नाम पर मुंह पूरा ढका हुआ था। कायदे से यदि गार्ड व मैनेजर सचेत हों तो बैंक में प्रवेश के समय एक बार हर आने वाले का मास्क हटवा कर देखे और इसी बीच वह कैमरे में कैद हो जाये, परन्तु इतना सचेत कोई नहीं रहता।

लापरवाह बैंक वालों को सचेत करने का काम पुलिस किया करती थी। पुलिस समय-समय पर जाकर बैंक के गनमैन को टाइट करने के साथ-साथ कैमरों व अलार्म की जांच भी किया करती थी, परन्तु आजकल इतनी कवायद करता कोई पुलिस अधिकारी नजर नहीं आता। नजर आये भी कैसे अब अपराध रोकने की अपेक्षा उनकी प्राथमिकतायें कुछ और ही हो गयी है।

देखी-सुनी

खबरीलाल

गरिमा मित्तल क्या जाना चाहती हैं

फरीदाबाद में इस समय पानी, सीवर जाम, सफाई, अवैध निर्माण, खराब सड़क, खोरी पुनर्वास और कई अन्य जन समस्याओं को लेकर शहर के हालात सरगर्म हैं। इन सभी समस्याओं का सीधा संबंध नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) से है। इसकी मुखिया आईएएस गरिमा मित्तल हैं। उनके पास स्मार्ट सिटी और एफएमडीए का भी काम है। रोजाना आंदोलन हो रहे हैं। तमाम पार्षदों ने उन्हें हटाने की मांग कर दी है। एमसीएफ में फैला भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं है। कई मामलों में गरिमा मित्तल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड लिया लेकिन ऊपर बैठे अफसरों और मंत्रियों ने कार्रवाई से रोक दिया। गरिमा मित्तल जिस तरह से अब सारी समस्याओं से डील कर रही हैं, उससे लगता है कि अब वो खुद भी एमसीएफ से हटना चाहती हैं। पहले तो उनके डीसी यशपाल यादव से मतभेद हुए। खैर, किसी तरह उन्होंने एमसीएफ में जमने की कोशिश की तो पार्षद परेशान करने लगे। मंत्रियों के फोन आने लगे। बीच में उन्होंने एमसीएफ मुख्यालय में बैठना ही बंद कर दिया था और एमसीएफ की फाइलें स्मार्ट सिटी के दफ्तर से निपटाई जा रही थीं। लेकिन बात बनी नहीं। खबरीलाल को पता चला है कि उन्होंने चंडीगढ़ में अब आला अफसरों से कहना शुरू कर दिया है कि एमसीएफ में कोई पूर्णकालिक कमिश्नर भेजा जाए, ताकि वो स्मार्ट सिटी और एफएमडीए पर फोकस कर सकें। लेकिन आला अफसर यहां तदर्थ व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं कि ताकि माल चंडीगढ़ तक भी पहुंचता रहे। बहरहाल, जितना मुंह उतनी बातें। गरिमा मित्तल अब खुद एमसीएफ में नहीं रहना चाहती हैं।

जेजेपी तलाश रही दफ्तर

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) दफ्तर के नाम पर महान कुर्बानी देने के बाद अब फरीदाबाद में दफ्तर तलाश रही है। अभी तक उसका जिला कार्यालय नहीं बन पाया है। उसके नेता अपने घरों से दफ्तर चला रहे हैं। हुआ यह था कि जब हूडा ने किसी भी राजनीतिक दल को जिला दफ्तर बनाने के लिए आवेदन मांगे थे तो सबसे पहले जेजेपी ने आवेदन कर दिया था। लेकिन यह दरअसल, हूडा ने बीजेपी को फरीदाबाद में दफ्तर के लिए यह कागजी खानापूरी की थी लेकिन इसकी भनक जेजेपी को मिल गई थी। तब हूडा अफसरों ने जेजेपी नेताओं को बताया था कि हमें ऊपर से जिला भाजपा कार्यालय के लिए प्लॉट देने का सख्त निर्देश मिला है। इसलिए आप लोग अपनी अर्जी वापस ले लें। जेजेपी ने अपने गठबंधन दल के लिए यह कुर्बानी मंजूर कर ली। मजदूर मोर्चा के पाठक ये सब खबरें विस्तार से बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। हम यह भी बता चुके हैं कि कैसे नियम ताक पर रखकर हूडा ने बीजेपी को सेक्टर 15 में एपीजे स्कूल के पीछे बेशकीमती जमीन कोड़ियों के भाव दे दी। दफ्तर बनाने के लिए अब आगे की कहानी ये है कि जेजेपी बहुत शिद्दत से फरीदाबाद में अपना दफ्तर बनाने के लिए जगह खोज रही है। यहां तक कि उसके एक नेता ने तो कुछ पत्रकारों से ही इसमें सुझाव मांग लिया कि दफ्तर कहां खोलना ठीक रहेगा। जेजेपी नेताओं का कहना है कि फरीदाबाद में दलितों और मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे जुड़ना चाहता है लेकिन हमारे नेताओं के घर न मालूम होने और जिला दफ्तर न होने से वो भटकता रहता है। इसलिए अब हमें हर हालत में जिला दफ्तर खोलना है। जिन पत्रकारों से उस नेता ने सुझाव मांगा था, उन्होंने तो सुझाव नहीं दिया लेकिन अलबत्ता यह जानकारी जरूर हासिल कर ली कि फरीदाबाद बाईपास रोड पर उनकी नजर है। वहां जिला कार्यालय बनाया जा सकता है। जेजेपी के नेता अब पत्रकारों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां किस जमीन पर हाथ मारा जाए कि उनका वार खाली न जाए।

हम भी ट्रेड यूनियन हैं

आरएसएस-भाजपा की ओर से मजदूरों के बीच काम करने के लिए भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) अस्तित्व में आया था। बीएमएस आमतौर पर मुख्यधारा के ट्रेड यूनियन आंदोलन से बाहर रहता है। लेकिन जैसे ही किसी राज्य में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो बीएमएस सक्रिय हो जाती है। उसके नए-नए नेता और दफ्तर सामने आ जाते हैं। मंगलवार को बीएमएस ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन सौंपा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ज्ञापन में वही बातें दोहराई गईं जो कुछ दिन पहले सीटू, एटक, एचएमएस, इन्कलाबी मजदूर केंद्र आदि श्रमिक संगठनों ने अपने ज्ञापन में कहीं थीं। जिसमें डीसी रेट पर मजदूरी का भुगतान, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना जैसी मांगें थी। यह अच्छी बात है कि बीएमएस भी मजदूरों हितों के बारे में कभी-कभी सोच लेता है लेकिन जब राज्य में डबल इंजन सरकार हो यानी केंद्र में भी बीजेपी और हरियाणा में भी बीजेपी सत्तारूढ़ हो तो आखिर बीएमएस मांग किससे कर रहा है, वो ज्ञापन किस सरकार को दे रहा है। यह मजदूरों को सब्जबाग दिखाना ही है। बीएमएस को अच्छी तरह मालूम है कि हरियाणा या केंद्र सरकार उसे कितना महत्व देते हैं। महज अपना महत्व बताने, अपना अस्तित्व सिद्ध करने लिए बीएमएस के ऐसे प्रदर्शन ओछी हरकत माने जाएंगे। क्यों नहीं बीएमएस के केंद्रीय नेता सीधे केंद्र के श्रम मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं से बात करके मजदूरों की समस्याओं को हल कराते।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06